दैनिक भास्कर
आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार
हित) मूल्य ₹4.50
नागपुर, गुरुवार, 1 फरवरी, 2018 फाल्गुन कृष्ण पक्ष-1, 2074

सिंचाई : बढ़ेगी निधि तो किसान नहीं होंगे परेशान

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नागपुर इकाई की बजट से अपेक्षाएं

नगर संवाददाता | नागपुर.

बजट-2018 में यदि सिंचाई के क्षेत्र को खास तरजीह देते हुए अच्छी निधि दी जाती है तो सीधा लाभ देश भर के किसानों को मिलेगा। किसान आत्महत्या के लिए पहचाने जाने वाले विदर्भ को भी लाभ होगा। केंद्रीय बजट के एक दिन पहले दैनिक भास्कर से बातचीत में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, केंद्र के निदेशक एस.के. सिंह ने बताया कि नागपुर विभाग वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में शामिल है। यहां सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाने के लिए बजट से अपेक्षाएं हैं।

साथ ही श्री सिंह ने बताया कि वर्षा आधारित इलाकों के वैज्ञानिक कार्यक्रमों, अनुसंधानों के लाभ को किसानों तक पहुंचाना भी होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ पांच साल के भीतर किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि महत्वपूर्ण डेढ़ साल बीच चुके हैं, शेष समय का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए बजट में इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की अपेक्षाएं हैं। इसके लिए अधिक निधि का आवंटन किए जाने पर किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान संपन्न होगा। विदर्भ जैसे किसान आत्महत्या ग्रस्त इलाकों के लिए इसका अधिक लाभ मिल सकता है। कृषि क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र में आने से कृषि के साथ अन्य वैकल्पिक फार्मिंग मसलन बकरी पालन से लेकर अन्य मत्स्योत्पादन जैसे 9 सेक्टरों में किसान उत्पादन शक्ति बढ़ा सकता है।

पैदावार को शक्ति देना जरूरी

महाराष्ट्र कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्र में आता है। इन इलाकों में सिंचाई के संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि इन इलाकों के कृषि क्षेत्रों की पैदावार को शक्ति मिल सके। इन वर्षा आधारित इलाकों में सिंचाई को विकास करने से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, इससे उसमें निवेश की क्षमता विकसित होगी। यही नहीं, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान यूरिया आदि पर निर्भरता कम होगी, जिससे मृदा की गुणवत्ता बरकरार रहेगी और उसका नुकसान होना थम जाएगा। प्रधानमंत्री साइल हेल्थ कार्ड का अपना अलग लाभ है, लेकिन किसानों को निवेश में राज्य सरकारों का साथ मिलना जरूरी है। निरांचल परियोजना इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।

वर्ष 2020 तक संस्थान का लक्ष्य

- भूमि संसाधन सूचीकरण आंकड़ा आधारों के उपयोग के जरिए कृषि भूमि उपयोग नियोजन कार्यक्रम के दूसरे भाग के कार्यों को शुरू करना।
- आधारभूमि और नीतिगत मृदा संसाधन अनुसंधआन में वैश्विक नेतृत्व के लिए अविर्भाव।
- ग्राम फार्म स्तरीय समकालिक भूमि उपयोग योजनाओं का निर्माण विशेष तौर पर करना।
- मृदा संसाधन मानचित्रण, भूमि मूल्यांकन और भूमि उपयोग नियोजन में मृदा सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन और जीआईएस अनुप्रयोग की क्षमता विकास के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में प्रादुर्भाव करना।

संतरा उत्पादक किसानों के विकास के लिए निधि मिले : डॉ. श्रीवास्तव

जैविक खेती और कृषि मृदा कार्ड जैसे उपक्रमों को अधिक निधि उपलब्ध करा कर संतरा उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केंद्र के प्रभारी निदेशक व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. ए. के. श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि की इस शाखा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बीते वित्त वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा संतरा उत्पादक किसानों के लिए विशेष तौर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि रही।